

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260039
SG-DL-E-08012025-260039xxxGIDHxxx
xxxGIDExxxअसाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 322
No. 10]	DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946	[N. C. T. D. No. 322

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

एफ. सं. 11/14/एच-डीओपी/2024/03-13.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या एसओ 2506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 20 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्ति तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निदेशक अभियोजन, उप निदेशक अभियोजन (राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर) और सहायक निदेशक अभियोजन की शक्तियों एवं कार्यों को निम्नानुसार निर्दिष्ट करते हैं:

- निदेशक अभियोजन अपने नियंत्रण के अधीन कार्यरत अभियोजन अधिकारियों के माध्यम से 10 वर्ष से अधिक के दंडनीय अपराधों के संबंध में आरोप-पत्र/पुलिस रिपोर्ट की जांच करेगा। इसके अतिरिक्त, एक पर्यवेक्षी अधिकारी के रूप में, किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी आरोप-पत्र/पुलिस रिपोर्ट का परीक्षण/जांच कर सकता है।
- उप-निदेशक अभियोजन (राज्य स्तर पर) निदेशक अभियोजन को उनके शासकीय प्रशासनिक कामकाज में सहायता करने के अतिरिक्त सात वर्ष या उससे अधिक परन्तु दस वर्ष से कम के दंडनीय अपराध वाले मामलों की सुनवाई की निगरानी करेंगे, ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके तथा राज्य के विरुद्ध दोषमुक्ति और निर्वहन रिपोर्ट एवं आदेश की जांच की जा सके, उच्च न्यायालय में अपील दायर करने और पुनरीक्षण करने की सिफारिश के साथ उन्हें प्रस्तुत करें तथा विधि आदेश के अनुसार उस संबंध में निर्णय लिया जा सके।
- उप-निदेशक अभियोजन (जिला स्तर पर) जिले के प्रभारी होंगे तथा आरोप-पत्र का परीक्षण एवं जांच करेंगे तथा सात वर्ष या उससे अधिक परन्तु दस वर्ष से कम के लिए दंडनीय अपराध वाले मामलों की निगरानी करेंगे, अभियोजन अधिकारियों की सहायता से उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए तथा उपरोक्त अपराधों के संबंध में सभी

कार्यवाहियों के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

4. सहायक निदेशक अभियोजक, अभियोजक की सहायता से 7 वर्ष से कम की सजा वाले सभी मामलों से संबंधित आरोप-पत्रों/पुलिस रिपोर्टों की जांच करेंगे तथा ऐसे मामलों से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी होंगे।

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

यशपाल, उप-सचिव

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd January, 2024

F. 11/14/H-DOP/2024/03-13.—In exercise of the power conferred by sub-section (11) of Section 20 of The Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification bearing No. S.O.2506 (E) dated 28th June, 2024 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to specify the powers and functions of Director of Prosecution, Deputy Director of Prosecution (both at State Level as well as District Level) and Assistant Director of Prosecution as under:-

1. The Director of Prosecution shall scrutinize chargesheet/police reports in respect of the offences punishable for more than 10 years through the Prosecuting Officers working under his control. Further, as a supervisory officer, he may examine/ scrutinize any charge sheet/Police Reports in respect of any offence.
2. The Deputy Director of Prosecution (at State-Level) besides assisting the Director of Prosecution in his official administrative functioning shall monitor the trial of cases in which offence are punishable for seven years or more but less than ten years for ensuring their expeditious disposal and examine the acquittal and discharge reports and order against the State, submitted to him with the recommendation to file appeal and revision in the High Court and take the decision in that regard, as per mandate of Law.
3. The Deputy Director of Prosecution (at District Level) shall be the incharge of the District & shall examine and scrutinize the chargesheet and monitor the cases in which offences are punishable for seven years or more, but less than ten years with the assistance of the Prosecuting Officers, for ensuring their expeditious disposal and shall also be responsible for all the proceedings in respect of the offences mentioned above.
4. The Assistant Director of Prosecution shall scrutinize the charge sheets/police reports with the assistance of Prosecutor, pertaining to all cases wherein the punishment is less than 7 years and shall be responsible for all the proceedings in respect of such cases.

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

By Order in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
YASH PAL, Dy Secy.